www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 अंक – 317 जौनपुर बुधवार, 08 जुलाई 2026 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज – 4 मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

यूएन में भारत ने रखा एआई गवर्नेंस का विजन, सुरक्षित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के 'ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस' के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए सुरक्षित, भरोसेमंद, जिम्मेदार और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) व्यवस्था की वकालत की। उन्होंने कहा कि एआई का विकास मानव–केंद्रित, अधिकारों का सम्मान करने वाला और सभी देशों, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ की भागीदारी सुनिश्चित करने वाला होना चाहिए। कीर्ति वर्धन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा कि एआई के नियम और प्रबंधन ऐसे होने चाहिए जो इंसानों को केंद्र में रखें, सभी को साथ लेकर चलें और भरोसे पर आधारित हों। उन्होंने कहा कि एआई के विकास में मानवीय निगरानी, मानवाधिकारों का सम्मान और पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। साथ ही तकनीक और संसाधनों की कमी को दूर करना भी जरूरी है, ताकि ग्लोबल साउथ के देश भी एआई के भविष्य को आकार देने में प्रभावी भूमिका निभा सकें। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है, जो सुरक्षित, भरोसेमंद, जिम्मेदार और सभी के लिए समावेशी हो। उन्होंने कहा कि एआई का विकास वैश्विक सहयोग और साझा जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, ताकि इसका लाभ पूरी मानवता तक पहुंच सके।

कृषि उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने शुरू की 'प्रगति' पहल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को 20,000 कृषि उद्यमियों को सशक्त बनाने और 20 लाख किसानों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'प्रगति' पहल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित कृषि क्षेत्र और समृद्ध गांवों के बिना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार का ध्यान केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती की लागत कम करना, किसानों की आय बढ़ाना, फसल विविधता को बढ़ावा देना और कृषि को अधिक लाभदायक बनाना भी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए केवल पारंपरिक खेती पर्याप्त नहीं है। इसके लिए मूल्यवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना जरूरी है। कृषि मंत्री ने कहा कि 'प्रगति' पहल इसी सोच का विस्तार है। इसके माध्यम से किसानों को प्रौद्योगिकी, कृषि मशीनीकरण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और बेहतर बाजार पहुंच से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी आय बढ़ाने के नए अवसर तैयार होंगे। अधिकारी के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन (एसबीआईएफ) और गेट्स फाउंडेशन सहित कई संस्थानों के सहयोग से तैयार यह कार्यक्रम छोटे किसानों के जीवन स्तर में सुधार है।

भारत की विकास यात्रा यानी 1.4 अरब लोगों की आगे बढ़ती उम्मीदें - प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर लगातार चुनौतियों और संकटों के बावजूद भारत एक के बाद एक सुधारों के जरिए तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा का अर्थ 1.4 अरब लोगों की आगे बढ़ती उम्मीदें और आकांक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गांव से लेकर शहर तक हर भारतीय में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने का विश्वास पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति अचानक नहीं हुई है, बल्कि लगातार किए गए सुधारों और बेहतर प्रदर्शन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के मंत्र के साथ देश आगे बढ़ रहा है। इसी सोच ने भारत को तेजी से बदलने और वैश्विक स्तर पर मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की कार्यक्रम में मौजूदगी का स्वागत करते हुए कहा कि यह दोनों देशों के बीच गहरे रिश्तों का प्रतीक है। उन्होंने इंडोनेशिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि प्रवासी भारतीय भारत और इंडोनेशिया के बीच मित्रता की मजबूत कड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महानदी में केले के तने से बनी नावें तैराने की परंपरा, वायांग कुलित के माध्यम से महाभारत का मंचन और देवी श्री की पूजा जैसी परंपराएं भारत और इंडोनेशिया के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों की जीवंत मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का रिश्ता जितना प्राचीन है, उतना ही समृद्ध भी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इंडोनेशिया और पूरे आसियान क्षेत्र में विकास और समृद्धि का मजबूत साझेदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया दोनों ही तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और दोनों देशों के पास रुकने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज वैश्विक विकास की प्रमुख ताकत बन चुकी है।

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनर्गठन किया गया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) का पुनर्गठन किया है। यह आयोग लगभग तीन वर्षों से शीर्ष स्तर के पदों के रिक्त होने के कारण निष्क्रिय पड़ा था। सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने एक अध्यक्ष और चार सदस्यों की नियुक्ति करके आयोग का पुनर्गठन किया है, एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।ये नियुक्तियां बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2008 और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी संबंधित अधिसूचना के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई हैं। अधिसूचना के अनुसार, ओम प्रकाश व्यास को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बयान में कहा गया है कि राहुल गौतम, कुंदन कांस्कर, स्वाति गुप्ता और मोनिका शर्मा को आयोग के सदस्य नियुक्त किया गया है।सभी नियुक्तियां संबंधित नियुक्त व्यक्तियों के पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी। प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। हालांकि, यदि निर्धारित आयु सीमा कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरी हो जाती है, तो कार्यकाल उसी तिथि से समाप्त हो जाएगा। बयान में कहा गया है कि अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 60 वर्ष है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और अवसरों से भरपूर बचपन का अधिकार है।उन्होंने कहा कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

भारत की नजर 179 अरब डॉलर के खिलौना बाजार पर, निर्मला सीतारमण ने रखा 25प्रतिशत हिस्सेदारी का लक्ष्य

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को भारतीय खिलौना उद्योग से वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत को वर्ष 2032 तक 179 अरब डॉलर तक पहुंचने वाले वैश्विक खिलौना बाजार में 25% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार की संभावनाओं के साथ–साथ भारतीय उद्योग को अंतरराष्ट्रीय अवसरों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। राष्ट्रीय राजधानी में टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल बी2बी एक्सपो 2026 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का घरेलू खिलौना बाजार वर्ष 2034 तक करीब 5 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन उद्योग को इससे कहीं बड़े वैश्विक बाजार को ध्यान में रखकर रणनीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैश्विक खिलौना कारोबार में भारत के लिए व्यापक अवसर मौजूद हैं और देश को अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए कड़े गुणवत्ता मानकों और नियामकीय सुधारों ने भारतीय खिलौना उद्योग को नई दिशा दी है। उन्होंने बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने निगरानी और प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत किया है, ताकि देश में केवल सुरक्षित और प्रमाणित खिलौनों की बिक्री सुनिश्चित हो सके।

सीएम योगी ने कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का किया शुभारंभ

वाराणसी, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी से प्रदेश के शिक्षकों व उनके परिजनों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का तोहफा दिया। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल बड़ालालपुर में सुबह 10 बजे से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लागू होने के साथ ही प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। योजना में नियमित शिक्षकों के साथ शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइया और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। सीएम योगी ने योजना का शुभारंभ करने के साथ ही माध्यममिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा के सभी शिक्षकों और बच्चों को हृदय से बधाई दी। कहा कि तीन योजनाएं हैं, कैशलेस चिकित्सा, डिबीटी, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। आपने मांगा नहीं लेकिन आपने स्वास्थ्य की चिंता हमें है। इसमें 12 लाख शिक्षक लाभान्वित हो रहे हैं, सबको बधाई देते हुए आपका अभिनंदन भी करता हूं। बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों को जो धनराशि हस्तांतरित की जा रही है प्रत्येक छात्र 1200 रुपये दिया जा रहा है। हमारा दायित्व है कि विद्यालय अच्छा हो, स्वच्छ हो, आंतरिक अनुशासन बनाए। छात्र पूरी यूनिफॉर्म में आएं, इसके लिए अभिभावकों से बात करें। सीएम ने कहा कि कल बारिश हुई तो बच्चे उसी में नहा रहे थे, अभिभावकों को उन्हें समझाना चाहिए, बच्चे अबोध हैं। हम बताएं कि तीन दिन एक और तीन दिन दूसरा यूनिफार्म पहनो, घर के कपड़े दूसरे हों। यह बच्चों को बताना हमारा दायित्व है, यह उनके लिए प्रेरणा होगी। आज 1320 करोड़ रुपये भेजे गए। नागरिक के अलावा शिक्षकों का दायित्व है कि हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएं। निपुण भारत के तहत हर बच्चे योग्य बनाए जाएं, ये पीएम मोदी का विजन है। सीएम ने कहा कि आज एक एमओयू स्टेट बैंक के साथ किया।

फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए जज उपलब्ध कराने को हाईकोर्ट के संपर्क में सरकार - सीएम फडणवीस

मुंबई, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में जानकारी दी कि महाराष्ट्र में स्वीकृत 138 फास्ट ट्रैक अदालतों में से फिलहाल केवल 58 ही कार्यरत हैं। बाकी अदालतों के लिए न्यायाधीश उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार लगातार हाईकोर्ट के साथ संपर्क में है। सरकार विधायक राहुल कुल के प्रश्न का जवाब देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्यभर में कुल 138 फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की योजना बनाई गई थीं, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति पूरी तरह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण अभी केवल 58 अदालतें ही शुरू हो पाई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष से सरकार लगातार पत्राचार और मुख्य न्यायाधीश के साथ संयुक्त बैठकों के माध्यम से स्वीकृत अदालतों के लिए न्यायाधीश उपलब्ध कराने का अनुरोध कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार को बताया है कि नए न्यायाधीशों की भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी स्वीकृत फास्ट ट्रैक अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी जाएगी।उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अदालतों की आवश्यकता का निर्धारण हाईकोर्ट की एक समिति लंबित मामलों की संख्या के आधार पर करती है। यदि पुणे या किसी अन्य स्थान से नई अदालतों की मांग आती है तो लंबित मामलों का आकलन कर आवश्यकता अनुसार नई अदालतों को मंजूरी दी जाएगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि निचली अदालतों में बड़ी संख्या में रिक्त पद होने के कारण न्याय मिलने में गंभीर देरी हो रही है।उन्होंने बताया कि तब तक कुछ अदालतों को विशेष मामलों की सुनवाई के लिए 'डिजिग्नेटेड' दर्जा दिया गया है, लेकिन उन्हें अन्य सामान्य मामलों की भी सुनवाई करनी पड़ती है। पुणे और राज्य के अन्य हिस्सों में न्यायिक ढांचे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 से 12 वर्षों में महाराष्ट्र में सत्र न्यायालयों और अतिरिक्त जिला न्यायालयों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है।

आंध्र प्रदेश ने 9,076 करोड़ रुपए के निवेश वाली 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी

अमरावती, (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) ने मंगलवार को 9,076 करोड़ रुपए के निवेश वाली 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) की बैठक में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनसे 10,531 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।सरकार एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, स्वीकृत प्रस्तावों में विशाखापत्तनम जिले के कपुलुप्पाडा में अदाणी फाउंडेशन की 2,200 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश वाली परियोजना भी शामिल है। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे औद्योगीकरण को बढ़ावा दें ताकि कृषि परिवारों को अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकें और वे उद्यमी बन सकें। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया और एथेनॉल की बढ़ती मांग का लाभ उठाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एथेनॉल की मात्रा को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने से मक्का किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।उन्होंने अधिकारियों को एथेनॉल उत्पादन क्षेत्र में निवेश को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल के मिश्रण की मांग में काफी वृद्धि होगी।मुख्यमंत्री नायडू ने अधिकारियों को एथेनॉल, मीथेन और विमानन ईंधन को शामिल करते हुए एक व्यापक नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने धन सृजन और चक्रीय अर्थव्यवस्था को सरकार की विकास रणनीति के प्रमुख स्तंभ बताया। मुख्यमंत्री ने बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

असम में छोटे उद्योगों को बड़ी राहत, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को मिलेगा नया बल

असम, (एजेंसी)। असम सरकार ने कारोबार को बढ़ावा देने और उद्यमियों के लिए नियमों को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में छोटे और गैर–प्रदूषणकारी उद्योगों को कारोबार शुरू करने के लिए पहले तीन वर्षों तक किसी सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बेहतर बनाना है। सरकार चाहती है कि नए उद्यमी अपना समय सरकारी मंजूरियां लेने में नहीं, बल्कि अपने कारोबार को मजबूत करने और नई संभावनाएं पैदा करने में लगाएं। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "हम असम में कारोबार करना और आसान बना रहे हैं। छोटे और गैर–प्रदूषणकारी उद्योग अब पहले तीन वर्षों तक बिना सरकारी मंजूरी के अपना काम शुरू कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे उद्यमी मंजूरियों के पीछे भागने के बजाय लोगों के लिए मूल्य और अवसर पैदा करने पर ध्यान दें।" सरकार का मानना है कि इस फैसले से स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा पहली बार कारोबार शुरू करने वाले उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा। खासतौर पर ऐसे उद्योग, जिनका पर्यावरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, अब तेजी से अपनी गतिविधियां शुरू कर सकेंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह फैसला असम में व्यापार–अनुकूल माहौल तैयार करने, अधिक निवेश आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला मे तीन आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू,होंगे कई बड़े खुलासे

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है।मामले की तह तक पहुंचने के लिए अयोध्या पुलिस ने जेल में बंद आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।बुधवार को सुबह पुलिस टीम तीनों आरोपियों को जिला कारागार से कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस लाइन लेकर पहुंची, जहां उनसे आमने–सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है।जांच अधिकारियों का मानना है कि तीनों आरोपियों से एक साथ पूछताछ करने पर कथित साजिश, चढ़ावे की रकम के लेनदेन, धन के बंटवारे और इस पूरे प्रकरण में शामिल अन्य लोगों की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं।पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आएंगे, जो अब तक की जांच को नई दिशा देंगे।सूत्रों के अनुसार पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस आरोपियों को उन स्थानों पर भी ले जा सकती है।जहां कथित रूप से चढ़ावे की रकम और अन्य सामान का बंटवारा किया गया था।इसके अलावा आरोपियों के घरों और अन्य संभावित ठिकानों पर भी बरामदगी के उद्देश्य से पुलिस टीम छानबीन कर सकती है।इस हाई–प्रोफाइल मामले की जांच पहले से गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) की निगरानी में चल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और आरोपियों के बयानों का मिलान किया जा रहा है ताकि पूरे घटनाक्रम का सच सामने लाया जा सके। मामले में आगे भी कई अहम कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

संपादकीय

गैर–व्यापार बाधाएं

क्या अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के क्रम भारत अमेरिका को इस बात पर राजी कर पाएगा कि वह दोनों देशों के कारोबार में गैर–व्यापार बाधाएं खड़ी ना करे? भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर भारत में हैं। उन्हें आशा है कि मंगलवार और बुधवार की वार्ताओं के दौरान ऐसा हो जाएगा। मगर मुद्दा है कि क्या बातचीत का आधार द्विपक्षीय समझौते का वही फ्रेमवर्क है, जिस पर पिछले फरवरी में सहमति बनी थी? या बदली परिस्थितियों के मद्देनजर भारत फिर से सौदेबाजी कर रहा है? फ्रेमवर्क के एलान के बाद अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन के लगाए टैरिफ को असंवैधानिक ठहरा दिया था। उससे भारत सरकार को नया मौका मिला। उसका लाभ उठाकर वह उन आलोचनाओं को दूर कर सकती है, जिनसे इस मामले में उस पर समर्पण करने के आरोप लगे हैं। इस बीच अमेरिका ने उत्पादन में जबरिया मजदूरी के इस्तेमाल का आरोप लगाकर भारत के कई निर्यातों पर 12.5 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। अनुचित व्यापार व्यवहार के इल्जाम में उसने भारत के खिलाफ जांच चला रखी है। इनमें अत्यधिक औद्योगिक क्षमता और अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों के आरोप शामिल हैं। क्या समझौते को अंतिम रूप देने के क्रम भारत अमेरिका को इस बात पर राजी कर पाएगा कि वह दोनों देशों के कारोबार में ऐसी गैर–व्यापार बाधाएं खड़ी ना करे? भारत सरकार के रुख से इन मुद्दों पर दृढ़ रुख अपनाए जाने के संकेत नहीं मिले हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल में कहा कि भारत–अमेरिका ट्रेड डील को तब तक लागू नहीं किया जाएगा, जब तक भारत के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित नहीं हो जाता। इसका अर्थ है कि भारत पर लगने वाले शुल्क दरों को अमेरिका बांग्लादेश, वियतनाम और कुछ मामलों में चीन पर लगे टैरिफ से कुछ नीचे कर दे, तो डील भारत को स्वीकार्य हो जाएगा। स्पष्टतरू यह अपने मानक को काफी नीचे रखना है। फ्रेमवर्क में शामिल अमेरिका से अनिवार्य खरीदारी, ऊर्जा खरीद पर उसकी अनुचित शर्तों को मानने, और अपने बाजार को उसके लिए पूरी तरह खोलने जैसी शर्तें शामिल हैं। उन्हें फिर वार्ता की मेज पर लाने के बजाय भारत का निम्न मानक को अपनाना दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

खामेनेई युग का अंत

ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। जिसमें पूरे ईरान से लोग तो उमड़ पड़े ही हैं, साथ ही दुनिया के कई देशों के लोग उन्हें आखिरी बार श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। अली खामेनेई की अंतिम यात्रा सोमवार को राजधानी तेहरान में शुरू हुई। शहर की सड़कों पर लाखों लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे। जिस तरह से पूरे ईरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार पर लोग रोते–बिलखते दिख रहे हैं और जान के खतरे उठाकर भी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई का ईरान में क्या दर्जा था। वे केवल आधिकारिक तौर पर सुप्रीम लीडर नहीं थे, बल्कि उनके साहस और बेखौफ रवैये को देखकर आम ईरानी नागरिक उन्हें अपना सर्वोच्च नेता मानता था और उनके कहे को पत्थर की लकीर। शायद यही वजह है कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजरायल के हमले में आयतुल्लाह खामेनेई अपने कुछ परिजनों के साथ शहीद हुए, तो उनके न झुकने वाले जज्बे को हरेक ईरानी नागरिक ने अपने व्यवहार में उतार लिया और फिर अमेरिका–इजरायल के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को खुशफहमी थी कि वे ईरान पर आसान जीत दर्ज कर लेंगे, हमले के पहले ही दिन अली खामेनेई की हत्या करने के बाद ईरान में कोई नेतृत्व नहीं बचेगा और ईरानी पलटवार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अमेरिका और इजरायल का यह भ्रम बहुत जल्दी टूट गया। ईरान ने अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को सर्वोच्च नेता घोषित किया, वे अब तक सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति डा.मसूद पेजेश्कियान से लेकर विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गलीबाफ जैसे तमाम नेता लगातार सड़कों पर उतर कर जनता में हिम्मत बंधाते रहे और साथ ही ईरानी सेना अमेरिका और इजरायल पर जवाबी वार भी करती रही। इस युद्ध में ईरान को बेशक जान माल का बहुत नुकसान हुआ। आयतुल्लाह अली खामेनेई के अलावा अली लारीजानी जैसे नेता भी मारे गए, मिनाब की स्कूल में सौ से ज्यादा बच्चियां हमले का शिकार बनीं। लेकिन ईरान झुका नहीं, संघर्ष करता रहा। हालात ऐसे बने कि आखिर में अमेरिका को ईरान के साथ पहले अस्थायी युद्ध विराम और अब समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि ट्रंप की अकड़ अब भी खत्म नहीं हुई है।अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए कम से कम एक करोड़ लोग ईरान में अलग–अलग जगहों पर सड़कों पर आए हैं। इसे देखकर ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरानियों को रोता देखकर हैरानी हुई। उन्हें लगा था कि लोग खामेनेई से नफरत करते हैं। फिर खुद को सही साबित करने के लिए ट्रंप ने कहा, श्हो सकता है ये नकली आंसू हों।श इस बयान के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं या तो ट्रंप सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं कि उनके खामेनेई के विरुद्ध चलाए गए अभियान को जनता ने नकार दिया है या फिर उनमें वैश्विक मामलों की वाकई समझ नहीं है। वे अब भी इस मुगालते में हैं कि ईरान की सभ्यता को जमींदोज कर सकते हैं। याद कीजिए ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य न खोलने पर ईरान को सभ्यता मिटाने की धमकी दी थी। ऐसे बयानों से ट्रंप खुद ही अपनी मिट्टी पलीद करवा रहे हैं। बीबीसी के मुताबिक नकली आंसू वाले ट्रंप के दावे पर शोक मना रही 50 साल की महिला जहरा सफाई ने रॉयटर्स से कहा, श्हमने 47 साल पहले नकली आंसू बहाने के लिए क्रांति नहीं की थी। हमने अपने इतने शहीदों की कुर्बानी नकली आंसू बहाने के लिए नहीं दी।श्ऐसे बयान ट्रंप और नेतन्याहू को आईना दिखाने के लिए काफी हैं कि वे ईरान की सच्चाई समझ लें और युद्ध के रास्ते से पीछे लौट जाएं। मगर ये दोनों मगरूर नेता अब भी अपनी झूठी अकड़ में फैसले ले रहे हैं। जैसे खामेनेई के अंतिम संस्कार में तमाम वरिष्ठ ईरानी नेता और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस पर ट्रंप ने कहा कि ईरानी शासन के कई वरिष्ठ अधिकारी एक ही जगह मौजूद हैं। अमेरिका चाहे तो श्एक ही हमलेश में उन सभी को मार सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, श्हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा।श दरअसल ट्रंप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ईरान किसी एक नेता पर निर्भर नहीं है, ईरानी जनता ने यह साबित किया है कि देश बड़ा होता है कोई चेहरा नहीं। देश आदर्शों और सिद्धांतों पर चलता है। तो आयतुल्लाह अली खामेनेई ने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका की नीतियों के प्रतिरोध में जो सिद्धांत अपनाए ईरान अब भी उन्हीं पर चल रहा है, इसलिए उसे झुकाया नहीं जा सका।इधर बेंजामिन नेतन्याहू की नजर ईरान के साथ अब लेबनान पर टिकी है और हिज्बुल्लाह को खत्म करने के नाम पर लगातार लेबनान पर हमले हो रहे हैं। इस में अमेरिका को भी तकलीफ हो रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने जब इजरायल को कहा कि अमेरिका की बात सुनिए क्योंकि केवल हम ही आपका साथ दे रहे हैं ।

पंजाब ने बड़ी कीमत देकर शांति पाई, सतलुज के जरिये पुराने जख्मों को कुरेदना गलत है

नीरज

पंजाब के अशांत दौर, राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिव्यक्ति की बहस के बीच एक बार फिर विवादों के केंद्र में आई फिल्म सतलुज ने देशभर में तीखी बहस छेड़ दी है। अभिनेता दिलजीत दोसांझ अभिनीत यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। लेकिन यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि पंजाब के उस संवेदनशील और खून से सने दौर की कहानी को दोबारा सामने लाने की कोशिश है, जब आतंकवाद, अलगाववाद और सीमापार से प्रायोजित हिंसा ने पूरे राज्य को भय और अस्थिरता में धकेल दिया था। ऐसे समय में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इस फिल्म को भारत में ओटीटी मंच से हटाने का फैसला न केवल उचित दिखाई देता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी जिम्मेदार लोकतंत्र का कर्तव्य होता है। हम आपको बता दें कि यह फिल्म पहले घल्लूघारा नाम से शुरू हुई थी। बाद में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की आपत्तियों के बाद इसका नाम पंजाब–95 रखा गया और अंततः इसे सतलुज नाम से प्रदर्शित किया गया। फिल्म की विषयवस्तु पंजाब पुलिस के आतंकवाद विरोधी अभियान और उस दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर आधारित है। फिल्म में दिखाया गया है कि जसवंत सिंह खालड़ा ने 1984 से लेकर 1994 के बीच हजारों अज्ञात शवों के कथित अंतिम संस्कार के मामलों की जांच की थी। बाद में उनका खुद का अपहरण हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। अदालत ने इस मामले में कुछ पुलिसकर्मियों को दोषी भी ठहराया था। देखा जाये तो इन तथ्यों से किसी को इंकार नहीं हो सकता कि पंजाब ने उस दौर में अत्यंत पीड़ा झेली। हजारों निर्दोष लोग मारे गए, परिवार उजड़ गए और भय का वातावरण पूरे राज्य पर छाया रहा। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके दर्द के प्रति संवेदना व्यक्त करना हर संवेदनशील समाज का दायित्व है। लेकिन इसके साथ यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि उस समय पंजाब किस परिस्थिति से गुजर रहा था, इसे भी ईमानदारी से समझा जाए। सीमापार से आतंकवाद को खुला समर्थन मिल रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां पंजाब को अस्थिर करने के लिए सक्रिय थीं। अलगाववादी संगठन खुलेआम हथियारबंद हिंसा चला रहे थे। पुलिसकर्मियों, पत्रकारों, नेताओं और आम नागरिकों की हत्याएं रोजमर्रा की खबर बन चुकी थीं। ऐसे भयावह दौर में पंजाब पुलिस ने जिस कठोर अभियान को चलाया, उसी के कारण राज्य धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट सका। उस समय के पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल को लेकर आज अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि अगर पंजाब पुलिस और सुरक्षा बल कठोर कार्रवाई नहीं करते, तो शायद पंजाब आज भी आतंकवाद की आग में झुलस रहा होता। जिन्होंने उस दौर को अपनी आंखों से देखा है, वह जानते हैं कि हालात कितने गंभीर थे। केपीएस गिल और उनकी टीम ने आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसी ने पंजाब को अलगाववाद और बंदूक की राजनीति से बाहर निकालने में निर्णायक भूमिका निभाई। आज कुछ राजनीतिक दल और कथित बुद्धिजीवी पुलिसिया कार्रवाई को केवल एकतरफा तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि उस समय पंजाब में किस दल की सरकार थी। उस समय राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर सत्ता किसके हाथ में थी और निर्णय कहां से लिए जाते थे, यह इतिहास का हिस्सा है। साथ ही जो लोग आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहे हैं, उन्हें अपने अतीत में भी झांकना चाहिए। खासतौर पर कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि आपातकाल के दौरान देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों कुचल दी गई थी? अखबारों पर सेंसरशिप क्यों लगाई गई थी? विपक्षी नेताओं को जेलों में क्यों डाला गया था? यदि आज कोई सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कोई कदम उठाती

है, तो उसे तानाशाही कहना इतिहास के साथ अन्याय होगा। इसी के साथ पंजाब में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी की भूमिका पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। जिस तरह उसके कुछ नेता सतलुज फिल्म के पक्ष में खुलकर बयान दे रहे हैं, उससे यह आशंका भी पैदा होती है कि कहीं यह प्रयास राज्य सरकार की कथित नाकामियों से जनता का ध्यान हटाने की रणनीति तो नहीं है। कहीं आम आदमी पार्टी यह तो नहीं चाहती कि विधानसभा चुनावों में उसके कामकाज की बजाय इतिहास की घटनाएं ही मुद्दा बन जायें? सभी को यह समझना होगा कि इतिहास से सीख लेना आवश्यक है, लेकिन इतिहास को वर्तमान पर इस तरह हावी कर देना कि भविष्य ही प्रभावित होने लगे, किसी भी राज्य और समाज के लिए उचित नहीं माना जा सकता। पंजाब को आज विकास, रोजगार, नशे के खिलाफ कड़े कदम और कानून व्यवस्था सुध ारने जैसे वास्तविक मुद्दों पर आगे बढ़ने की जरूरत है, न कि पुराने घावों को बार बार कुरेदकर राजनीतिक लाभ लेने की।` सामाजिक और ध ार्मिक तानेबाने को बिगाड़ने की कोशिशें पहले भी होती रही हैं और आज भी दुश्मन ताकतें मौके की तलाश में रहती हैं। ऐसे में पुराने घावों को इस प्रकार कुरेदना, जिससे समाज में नई वैमनस्यता पैदा हो, बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि किसी भी संवेदनशील विषय को बिना व्यापक सामाजिक परिणामों पर विचार किए प्रस्तुत कर दिया जाए। फिल्म के प्रदर्शन को लेकर जिस प्रकार विवाद बढ़ा, उसने यह भी दिखाया कि ओटीटी मंचों के लिए स्पष्ट और कठोर नियमों की आवश्यकता है। फिल्म को केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड ने अनेक कट लगाने के सुझाव दिए थे। पहले 21 कट और बाद में 120 से अधिक संशोधनों की बात सामने आई। इसके बावजूद फिल्म निर्माताओं ने नया नाम देकर इसे ओटीटी मंच पर जारी कर दिया। ऐसे में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करना स्वाभाविक था। यदि किसी सामग्री से सामाजिक तनाव या अलगाववादी भावनाओं को हवा मिलने की आशंका हो, तो सरकार का कर्तव्य है कि वह समय रहते कदम उठाए। दिलचस्प बात यह भी रही कि अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने स्वयं पहले ही आशंका जता दी थी कि फिल्म को भारत में हटाया जा सकता है। बाद में उन्होंने लोगों से इसे डाउनलोड कर दूसरों को दिखाने की अपील भी की। यह रवैया कई सवाल खड़े करता है। जब मामला इतना संवेदनशील हो, तब जिम्मेदार कलाकारों को समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने का संदेश देना चाहिए, न कि विवाद को और भड़काने वाला व्यवहार करना चाहिए। यह सही है कि इतिहास के कठिन अध यायों पर चर्चा होनी चाहिए। पीड़ितों को न्याय और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन किसी भी चर्चा का उद्देश्य समाज को बांटना नहीं, बल्कि सीख देना होना चाहिए। पंजाब ने बहुत खून बहते देखा है। वहां की नई पीढ़ी शांति, विकास और भाईचारे के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे समय में किसी भी प्रकार की ऐसी प्रस्तुति, जिससे अलगाववादी मानसिकता को बल मिले या सुरक्षा बलों के मनोबल पर आघात पहुंचे, उसे गंभीरता से देखने की आवश्यकता है।

योगी के घर लंच, केशव के घर चाय और ब्रजेश के घर आम पार्टी के जरिये भाजपा ने दिया बड़ा संदेश

नीरज

उत्तर प्रदेश की राजनीति में रविवार को केवल दावतें नहीं हुईं, बल्कि भाजपा ने लंच, मैंगो पार्टी और चाय पार्टी के जरिए 2027 की चुनावी एकजुटता का खुला संदेश दिया। देखा जाये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ दृश्य केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होते बल्कि वे सीधे सत्ता और संगठन के भीतर के संदेश बन जाते हैं। वर्ष 2022 के चुनावों से ठीक पहले जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे थे, उसी राजनीतिक संकेत को भाजपा ने इस बार और ज्यादा व्यापक रूप में दोहराया। फर्क सिर्फ इतना रहा कि इस बार तस्वीर और भी ज्यादा मजबूत दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और वरिष्ठ नेताओं का साथ में लंच, फिर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के यहां मैंगो पार्टी और उसके बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर चाय पार्टी ने साफ कर दिया कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के मतभेद की अटकलों को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। योगी, केशव और ब्रजेश की साझा मौजूदगी ने केंद्रीय नेतृत्व को यह भरोसा दिला दिया कि 2027 का चुनाव भाजपा पूरी राजनीतिक एकजुटता, संगठनात्मक तालमेल और साझा रणनीति के साथ लड़ेगी। सत्ता, संगठन और सामाजिक समीकरणों को एक मंच पर लाकर भाजपा ने यह संदेश दे दिया कि चुनावी बिगुल बज चुका है और पार्टी अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। देखा जाये तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दो दिवसीय लखनऊ दौरे ने यह साफ कर दिया कि पार्टी ने 2027 के मिशन की औपचारिक शुरुआत कर दी है। संगठनात्मक बैठकों, रणनीतिक विमर्श और सहयोगी दलों के साथ लगातार संवाद के बीच रविवार का दिन राजनीतिक संदेशों से भरा रहा। दिन की शुरुआत भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ चाय पर चर्चा से हुई, जहां संगठन की पुरानी ताकत, पुराने अनुभव और आने वाले चुनाव की नई रणनीति पर गंभीर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि भाजपा इस बार चुनाव को केवल सत्ता बचाने की लड़ाई नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक अभियान के रूप में देख रही है। लेकिन असली राजनीतिक संदेश तब सामने आया जब औपचारिक बैठकों के बाद भाजपा नेतृत्व ने अपने अंदाज को पूरी तरह राजनीतिक प्रतीकों में बदल दिया। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेता उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पहुंचे, जहां आम पार्टी आयोजित की गई थी। राजनीतिक तपिश के बीच आम की मिठास ने माहौल को हल्का जरूर किया, लेकिन इसके भीतर छिपा संदेश बेहद गंभीर था। ब्रजेश पाठक ने सभी नेताओं का स्वागत किया और प्रदेश के प्रसिद्ध आम परोसे। माहौल में राजनीतिक तनाव की जगह सहज बातचीत, हंसी और आत्मीयता दिखाई दी। सबसे चर्चित क्षण तब आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में आम उठाया, उसे दांतों से छीलते हुए मुस्कुराए और फिर उसका स्वाद लिया। वहां मौजूद नेताओं के बीच ठहाके गूंज उठे। यह दृश्य केवल एक अनौपचारिक क्षण नहीं था, बल्कि भाजपा नेतृत्व की अंदरूनी सहजता और पारस्परिक विश्वास का सार्वजनिक प्रदर्शन भी था। आम पार्टी के बाद पूरा काफिला उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पहुंचा, जहां चाय पार्टी आयोजित की गई। यहां नितिन नवीन का पारंपरिक अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया और उन्हें भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गई। योगी आदित्यनाथ, बीएल संतोष, ब्रजेश पाठक और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने इस मुलाकात को और अधिक राजनीतिक महत्व दे दिया। दरअसल, भाजपा अच्छी तरह जानती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल विकास योजनाओं या चुनावी नारों से नहीं जीता जाता, बल्कि संगठनात्मक एकजुटता और सामाजिक समीकरणों की मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि 2022 से पहले जिस तरह योगी आदित्यनाथ का केशव मौर्य के घर जाना चर्चा का केंद्र बना था, उसी तरह इस बार भी वही तस्वीर दोहराकर भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी में कोई दूरी नहीं है, कोई खेमेबाजी नहीं है और पूरा नेतृत्व एक साथ खड़ा है। नितिन नवीन ने भी अपने पूरे दौरे के दौरान बार–बार यही संकेत दिया कि यह समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा के विस्तार का समय है। भाजपा की रणनीति साफ दिखाई दी। एक ओर संगठन को सक्रिय करना, दूसरी ओर राजग सहयोगियों को साथ लेकर चलना और तीसरी ओर नेतृत्व की एकजुट तस्वीर को जनता के सामने रखना। ताज होटल में आयोजित राजग सहयोगियों की बैठक में राष्ट्रीय लोक दल, निषाद पार्टी, सुभासपा और अपना दल के नेताओं ने जिस तरह 2027 में ऐतिहासिक जीत का दावा किया, उसने भाजपा की चुनावी तैयारियों को और स्पष्ट कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा 2027 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता विकास, सुशासन और सुरक्षा चाहती है, न कि गुंडाराज और परिवारवाद। देखा जाये तो भाजपा की पूरी कवायद का सबसे बड़ा संदेश यही था कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव केवल सीटों का संघर्ष नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक मनोबल, संगठनात्मक शक्ति और नेतृत्व की एकजुटता की भी परीक्षा होगा। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की एक साथ मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और पार्टी अब हर स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं, सहयोगियों और समर्थकों को यह भरोसा दिलाना चाहती है कि सत्ता और संगठन दोनों पूरी तरह एक सुर में हैं। लखनऊ में रविवार को दिखाई दी यह राजनीतिक तस्वीर केवल चाय और आम पार्टी की तस्वीर नहीं थी, बल्कि 2027 की चुनावी पटकथा का पहला सार्वजनिक दृश्य थी।

बिखरी हुई कंगाल कॉलोनी के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को हराने की कहानी

अभिनय

जब भी हम बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन सा है। तो बिना किसी किंतु–परंतु के एक ही नाम अमेरिका का याद आता है। अब आपमें से कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि रूस और चीन भी तो ताकतवर देश हैं। लेकिन ये देश कंपटीशन की उस लाइन में हैं, जिसे अमेरिका बहुत पहले पार कर चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है। इसकी जीडीपी 20 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी अमेरिका के पास है। दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां फिर चाहे एप्पल हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट सभी अमेरिकी की है। इन सभी चीजों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आपको यकीन हो जाएगा की अमेरिका ही इस दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की शुरुआत कैसे हुई? इस बगावत का हिंदुस्तान से क्या कनेक्शन था? अमेरिका का संविधान कैसे बना? कैसे तय हुआ कि 13 कॉलोनी मिलकर एक नया देश बनाएंगी? अमेरिका की आजादी को 4 जुलाई 2026 को 250 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर एमआरआई का दो एपिसोड्स की सीरिज लेकर आ रहे हैं। जिसमें आपको मालूम चलेगा कि अमेरिकी क्रांति और वहां की आजादी का जो आईडिया है उसकी पूरी यात्रा कैसे हुई। उनमें क्या–क्या पड़ाव थे। अगर आप इतिहास को देखें तो दुनिया की ताकत हर टाइम पीरियड में अलग अलग देशों यहां तक की महाद्वीपों के पास रही है। प्राचीन काल को देखें तो चीन, रोम और भारत तीन साम्राज्य दुनिया के सबसे ताकतवर हिस्से हुआ करते थे। 1800 तक दुनिया की पूरी इकोनॉमी भारत और चीन के ईर्द गिर्द घूमती थी। यहां से बड़े पैमाने पर सामान को यूरोप इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन इसके बाद जब मॉर्डन वर्ल्ड की शुरुआत हुई। यूरोप में इंडस्ट्रलाइजेशन आया तो यूरोप ने इन सब बड़ी ताकतों को अपने कब्जे में कर लिया। फिर चाहे वो हिंदुस्तान, चीन या फिर ऑटोमन सुल्तानों के कब्जे में रहा मीडिल ईस्ट ही क्यों न हो। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते न भारत न चीन न इंग्लैंड न फ्रांस सभी ताकतों को पीछे छोड़ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकवर देश बन गया। 1453 में कतन दुनिया पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया था जिससे यूरोप से ईस्टर्न कंट्रीज के ट्रेड रूट्स बंद हो गए थे जिसके बाद यूरोप के सेलर्स ने नए सी रूट्स ढूंढने शुरू कर दिए जिससे कि ईस्टर्न कंट्रीज के साथ यूरोप का ट्रेड किया जा सके भारत के लिए नए सी रूट की खोज में निकलस स्पीन का नाविक कोलंबस भटककर अटलांटिक ओशन को पार करता हुआ 1492 में एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच गया। कोलंबस ने इस नए कॉन्टिनेंट को भारत समझकर यहां के नेटिव लोगों को रेड इंडियन कहा। इसके बाद 1499 में इटालियन ट्रेवलर अमर्जी यो वेस्पो की इस कॉन्टिनेंट पर पहुंचा जिसके नाम पर ही यहां का नाम अमेरिका पड़ा। यह कॉन्टिनेंट मिनरल रिसोर्सेस से भरा पड़ा था और यहां की जमीन भी बेहद ही फर्टाइल थी, जिसके कारण यूरोप के देश में इसे अपनी कॉलोनी बनाने को लेकर होड़ मची हुई थी। सबसे पहले स्पेन के लोगों ने अमेरिका के नेटिव लोगों को गुलाम बनाकर फार्मिंग करनी चाही। लेकिन वहां के लोकल्स ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए अफ्रीका के लोगों को अमेरिका लाया गया और उन्हें गुलाम बनाकर उनसे खेती करवाई गई। इस तरह स्पेन ने अमरिका के कुछ जगहों पर अपनी कॉलोनी बना ली। फिर आया साल 1588 का जब स्पेन की नेवी और इंग्लैंड की नेवी के बीच भयानक युद्ध होता है और इंग्लैंड की नेवी को जीत मिलती है तो अब इंग्लैंड को अमेरिका में अपनी कॉलोनी बनाने का मौका मिल गया। नॉर्थ अमेरिका में इंग्लैंड ने अपनी पहली कॉलोनी जेम्स फस्ट के समय में 1600 साथ में बनाई जिसका नाम जेम्स टाउन रखा गया। फिर चार्ल्स फर्स्ट के समय कॉलोनी बनाने के काम तेजी में आया। 1630 में प्यूटन लोगों का एक ग्रुप नॉर्थ अमेरिका के बोस्टन में जाकर बस जाता है जिसके बाद धीरे–धीरे यूरोपियन भारी संख्या में अमेरिका में जाकर बस गए। 1607 से 1722 ईसवी आते–आते अमेरिका में ब्रिटिशर्स ने अपनी 13 कॉलोनी बना दी। कॉलोनी उस समय प्रॉपर्टी कमाने का एक बड़ा माध्यम था और यही कारण था कि यूरोपियन लगातार अमेरिका में जाकर बसने लगे। इसके साथ ही यूरोप में रिलीजन को लेकर हार्ड पॉलिसी थी। जिसके कारण भी यूरोपियन अमेरिका में आकर बसने लगे। सैन्यइतिहास इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल इजेशन की शुरुआत हो चुकी थी इसलिए वहां पर रॉ मटेरियल की बहुत जरूरत थी ऐसे में अमेरिका रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए सबसे सही जगह थी जहां रिसोर्स की कमी नहीं थी। इसके साथ ही इंग्लैंड को अपने तैयार प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक बड़ी मार्केट की भी जरूरत थी और ऐसे में अमेरिका में मजदूरों और किसानों की भी जरूरत थी उस समय इंग्लैंड में एक पॉलिसी के चलते वहां के कई किसान लैंडलेस हो गए क्रिमिनल्स और भिखारियों की संख्या इंग्लैंड में बढ़ती चली गई थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान ऐसे ही लोगों को ब्रिटिश कंपनी अपने खर्च पर अमेरिका ले जाती थी और उनसे मजदूरी करवाती थी इस तरह अमेरिक कॉलोनी में ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस अफ्रीका के साथ–साथ वहां के

नेटिव लोगों का ग्रुप बसा हुआ था इस तरह यहां पर एक मिक्स्ड कल्चर सोसाइटी का जन्म हुआ सभी के डिफरेंट कल्चर होने के बाद भी कॉमन प्रॉब्लम होने के चलते यहां के लोगों में काफी यूनिटी थी यही कारण है कि यहां के लोगों में डेमोक्रेटिक आइडिया का भी डेवलपमेंट होने लगा इसी बीच अमेरिका में कॉलोनी को लेकर इंग्लैंड और अन्य देश के बीच कई लड़ाइयां भी हुई 1649 से 1658 तक इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच तीन वॉर हुए इस वॉर में हॉलैंड को हार मिली जिसके चलते इंग्लैंड को न्यू एमस्टरडम मिला जिसका नाम बाद में न्यूयॉर्क रखा गया इसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कॉलोनी को लेकर टसल शुरू हुआ जिसमें 1713 में फ्रांस युद्ध हार गया जी हां दोस्तों जिसके चलते एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फ्रांस को स्टॉ केसिया नॉर्थ अमेरिका में हडसन की खाड़ी और न्यू फाउंडलैंड जैसी कॉलोनी से अपना कब्जा छोड़ना पड़ा लेकिन इसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कुछ कॉलोनी को लेकर लगातार टसल जारी रहा जिसके बाद अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे फेमस वॉर शुरू हुआ जिसे ये सेवन इयर्स वॉर के नाम से जाना जाता है यह 1756 से 1763 तक लगातार जारी रहा इस वॉर में फ्रांस की हार हुई।

शिक्षा सेवा चयन आयोग में हिंदी प्रवक्ता बने नितेश सिंह, क्षेत्र में खुशी की लहर

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जनपद के जलालपुर थाना क्षेत्र के भगरी गांव निवासी नितेश सिंह का चयन यूपीएससी, प्रयागराज द्वारा हिंदी प्रवक्ता पद पर होने से परिवार, शिक्षक समुदाय और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। नितेश सिंह वर्तमान में राज कॉलेज, जौनपुर में कार्यालय सहायक के पद पर कार्यरत हैं। नितेश सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य डॉ. सुवास सिंह (बी.आर.पी. इंटर कॉलेज,

जौनपुर) के भतीजे तथा राजकुमार सिंह के पुत्र हैं। उनके चयन की सूचना मिलते ही परिवार, शुभचिंतकों और शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना की। परिजनों ने इस सफलता का श्रेय भगवान रामेश्वर धाम की कृपा, नितेश सिंह की मेहनत, लगन और निरंतर अध्ययन को दिया। वहीं शिक्षक समुदाय और प्रधानाचार्य परिषद के सदस्यों ने कहा कि यह उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है और इससे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की नई ऊर्जा मिलेगी। नितेश सिंह की इस सफलता पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति से जौनपुर का नाम गौरवान्वित हुआ है। उनके चयन पर पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का वातावरण है और शुभकामनाओं का सिलसिला लगातार जारी है।

नई बाइक खरीदने पर दो आईएसआई हेलमेट लेना अनिवार्य, सड़क सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब नई दोपहिया वाहन खरीदने वाले प्रत्येक ग्राहक को वाहन के साथ दो आईएसआई प्रमाणित हेलमेट खरीदना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना और हेलमेट के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। सड़क सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों के अनुसार अधिकांश सड़क हादसों में सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण लोगों की मृत्यु होती है। अक्सर देखा जाता है कि चालक तो हेलमेट पहनता है, लेकिन पीछे बैठा व्यक्ति बिना हेलमेट यात्रा करता है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने पर उसके गंभीर रूप से घायल होने या जान गंवाने का खतरा अधिक रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी दोपहिया वाहन डीलरों को वाहन बिक्री के समय दो मानक हेलमेट उपलब्ध कराने के

निर्देश दिए गए हैं। जौनपुर में भी यातायात पुलिस समय–समय पर हेलमेट जांच अभियान चलाती है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग बिना हेलमेट अथवा केवल चालक के हेलमेट पहनकर यात्रा करते हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह व्यवस्था तभी प्रभावी होगी, जब लोग इसे केवल औपचारिकता न मानकर अपनी आदत का हिस्सा बनाएंगे।इस संबंध में बुधवार को जानकारी देते हुए एआरटीओ (प्रवर्तन) सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सभी दोपहिया वाहन विक्रेताओं को आईएसआई प्रमाणित हेलमेट उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए चालक और पीछे बैठने वाले दोनों व्यक्तियों का हेलमेट पहनना आवश्यक है। वहीं, वेंकटेश हुंडई के अधिष्ठाता मनोज अग्रहरी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक दोपहिया वाहन खरीदार को दो हेलमेट दिए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हेलमेट निरूशुल्क नहीं होंगे, बल्कि वाहन खरीदते समय ग्राहकों को उनका मूल्य भी चुकाना होगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि प्रत्येक यात्रा के दौरान दोनों हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों में कमी लाई जा सके।

एनजीबी यूनिवर्सिटी के नए कुलपति बने प्रो. बीवी तिवारी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अश्वनलाइन हुआ अभिनंदन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संस्थान के डीन एवं पूर्व कार्यवाहक कुलपति रहे प्रो. बीवी तिवारी को नेहरू ग्राम भारती विश्व विद्यालय प्रयागराज का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर मंगलवार को पूर्वांचल विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षाविदों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका अभिनंदन किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी के प्रतिष्ठित शिक्षाविद प्रो. तिवारी ने वर्ष 1986 में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की से एमटेक तथा वर्ष 1993 में यूनिवर्सिटी आफ लखनऊ से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। चार दशक से अधिक के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनुभव के दौरान उन्होंने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में डीन, विभागाध्यक्ष और कार्यवाहक कुलपति सहित कई महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। इसके अलावा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद तथा गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में भी उन्होंने अध्यापन, अनुसंधान और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। ऑनलाइन आयोजित अभिनंदन समारोह में पूर्व कुलपति प्रो. डी.डी. दुबे ने कहा कि प्रो. बीवी तिवारी का अनुभव और नेतृत्व विश्वविद्यालय को नई दिशा देगा। अपने संबोधन में प्रो. तिवारी ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता विश्वविद्यालय को शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान, नवाचार, अनुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायी प्रशासन का केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान की प्रगति सामूहिक प्रयास, समर्पण और सकारात्मक कार्य संस्कृति से ही संभव है। कार्यक्रम में प्रो. हरिश्चंद्र पुरोहित, प्रो. एस.के. सिन्हा, मनु प्रसाद आचार्य, डॉ. हरिश्चंद्र मौर्य, प्रो. ए.के. श्रीवास्तव, प्रो. सौरभ पाल, प्रो. अजय द्विवेदी, प्रो. राजकुमार सोनी, प्रो. दिग्विजय सिंह, प्रो. मनोज मिश्रा तथा डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर सहित अनेक शिक्षकों ने प्रो. तिवारी को शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का संचालन डॉ. विवेक सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. प्रमोद सिंह कौशिक ने किया। अंत में प्रो. तिवारी ने सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

बच्चों का भविष्य संवारना ईश्वरीय कार्य - सुषमा खर्कवाल

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। भारतीय स्टेट बैंक हर भारतीय का बैंक होने का दायित्व निभाते हुए अपने ग्राहकों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के अलावा उन्हें वित्तीय रूप से जागरूक बनाते हुए राष्ट्र निर्माण में एक सहभागी की भूमिका निभा रहा है। अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत एसबीआई समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर सुधारने व उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के तहत बैंक ने राज्य के कई प्राथमिक विद्यालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन हेतु वहां अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बैंक ने मंगलवार को नगर निगम, लखनऊ द्वारा संचालित अमीनाबाद इंटर कालेज में अध्ययनरत 2000 छात्रों को बैठने की उत्तम व्यवस्था हेतु गुणवत्तायुक्त 500 स्टील बेंच प्रदान किए। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि " बच्च्चे भविष्य्य की नींव होते हैं और उनका भविष्य्य संवारना ईश्वरीय कार्य है। इसलिए हम नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों को बेहतरीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छा स्कूल और मां की परवरिश बच्चों का भविष्य संवारती है।" इस अवसर पर उपस्थिति विशिष्ट अतिथि नगर आयुक्ध्त गौरव कुमार ने कहा कि "नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों के सभी कक्षाओं को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।" इस कार्यक्रम में एसबीआई के उप महाप्रबंधक धीरज कुमार ने कहा कि बैंक अखिल भारतीय स्ध्तर पर अपने लाभ में से 700 करोड़ से अधिक की राशि समाज के कल्याणकारी कार्यों पर व्यय करती है। बैंक ने प्राथमिक विद्यालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्रों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों के उन्नयन के साथ–साथ सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल के तहत कन्याओं की शिक्षा एवं स्वच्छता की दिशा में अनेकों कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसी क्रम में आज बच्चों की पढ़ाई के लिए 500 स्टील बेंच उपलब्ध कराना हमारे लिए केवल एक औपचारिक दायित्व नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारी संपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। हम आगे में इस दिशा में हर संभव प्रयास करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त अरूण कुमार गुप्ध्ता, उप नगर आयुक्त रश्मि भारती, क्षेत्रीय पार्षद मुकेश सिंह के अलावा अमीनाबाद इंटर कालेज के प्राचार्य साहब लाल मिश्र भी उपस्थित रहे। एसबीआई की ओर से इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रबंधक अवंतिका सिंह मिश्रा, सरकारी व्यवसाय शाखा की मुख्य प्रबंधक ऋचा द्विवेदी एवं अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

जीआरपी जौनपुर ने बरामद किए 88 गुम मोबाइल, 19 लाख के फोन मालिकों को लौटाए

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में ट्रेनों में यात्रा के दौरान गुम हुए मोबाइल फोन तलाशने में जीआरपी जौनपुर को बड़ी सफलता मिली है। जीआरपी पुलिस ने सर्विलांस की मदद से 88 गुम मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 19 लाख रुपये बताई जा रही है। बरामद मोबाइलों में से 55 फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए गए, जबकि शेष मोबाइल उनके मालिकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। बुधवार को दोपहर रेलवे वाराणसी के पुलिस उपाधीक्षक कुंवर प्रभात सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जीआरपी जौनपुर द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत यह सफलता हासिल हुई है। आधुनिक तकनीक और सर्विलांस सेल की मदद से गुम हुए मोबाइल फोन खोजकर सुरक्षित बरामद किए गए। मोबाइल वापस पाने के लिए जौनपुर के अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों तथा अन्य राज्यों से भी लोग जीआरपी थाने पहुंचे। अपना खोया हुआ मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने जीआरपी जौनपुर की कार्यशैली की सराहना करते हुए पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। इस अभियान को जीआरपी अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी सुनील कुमार गौड़ के नेतृत्व में संचालित किया गया। अभियान में सर्विलांस सेल और जीआरपी की टीम ने समन्वय के साथ काम करते हुए मोबाइल बरामद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीआरपी अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि ट्रेन यात्रा के दौरान अपने मोबाइल और अन्य कीमती सामान का विशेष ध्यान रखें तथा मोबाइल गुम होने पर तत्काल संबंधित जीआरपी थाने या ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

शिक्षकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध - राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ बुधवार को वाराणसी से किया गया। इसका जौनपुर के कलेक्ट्रेट प्रेक्षागृह में सजीव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना का शुभारंभ हुआ। साथ ही विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रति छात्र 1,200 रुपए की धनराशि भी अंतरित की गई। जौनपुर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, डॉ. अजय सिंह तथा जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. ने दीप प्रज्ज्वलित एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और पौधा भेंटकर किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने बेसिक शिक्षा विभाग के 10 शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, स्पेशल एजुकेटरों और रसोइयों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के प्रतीकात्मक कार्ड वितरित किए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के पांच शिक्षकों को भी योजना के कार्ड प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और शिक्षा विभाग से जुड़े सभी कार्मिकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस योजना से प्रदेश के लगभग 12 लाख शिक्षकों एवं उनके परिवारों को ६5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। इससे गंभीर बीमारी या आपात स्थिति में बेहतर और समयबद्ध इलाज सुनिश्चित होगा तथा आर्थिक बोझ भी कम होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना केवल स्वास्थ्य सुविधा नहीं, बल्कि गुरुजनों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का सशक्त माध्यम है। समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उनके स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं संविदा कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर चयनित स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों का सम्मान भी किया गया।

चार-पांच वर्षो से नहीं बदले परीक्षा केंद्र, आगामी सत्र में होगा पुनर्निर्धारण - परीक्षा नियंत्रक

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में परीक्षा केंद्र निर्धारण की व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है। विश्वविद्यालय से संबद्ध जौनपुर और गाजीपुर के करीब 300 महाविद्यालयों के परीक्षा केंद्र पिछले चार से पांच वर्षों से नहीं बदले गए हैं। इसे लेकर परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व में परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक दो वर्ष में परीक्षा केंद्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता था। इसका मकसद किसी एक महाविद्यालय को लगातार परीक्षा केंद्र बनाए जाने की परंपरा समाप्त करना और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना था। हालांकि, पिछले कई वर्षों से एक ही महाविद्यालयों को लगातार परीक्षा केंद्र बनाए जाने से शिक्षा जगत में तरह–तरह की चर्चाएं हो रही हैं। शिक्षाविदों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों का नियमित परिवर्तन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लंबे समय तक एक ही केंद्र बनाए रखने से पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उनका यह भी मानना है कि यदि केंद्र निर्धारण की नीति में कोई बदलाव किया गया था, तो इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए थी। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने आगामी परीक्षा सत्र में केंद्र निर्धारण की व्यवस्था में बदलाव के संकेत दिए हैं। बुधवार को इस संबंध में पूछे जाने पर परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मेडिकल कालेज जौनपुर द्वारा कृषक विकास समित निःशुल्क वृद्धाश्रम सैय्यद अलीपुर में निः शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर के प्रधानाचार्य प्रो0 आर0 बी0 कमल के दिशा निर्देश में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो0 ए0ए0 जाफरी एवं जनरल मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डा0 विनोद कुमार के कुशल मार्ग दर्शन में कृषक विकास समित निःशुल्क वृद्धाश्रम सैय्यद अलीपुर, सदर जौनपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह स्वास्थ्य शिविर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जनहित एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित होकर वृद्धाश्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने हेतु मेडिकल कालेज जौनपुर प्रशासन से अनुरोध किया। परिषद के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सको की टीम को भेजा गया जिसमें नेत्र रोग विभाग, जनरल मेडिसिन विभाग, क्षय एवं वक्ष रोग विभाग (टीबी एवं चेस्ट), सामुदायिक चिकित्सा विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग सहित विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चिकित्सकों ने रोगियों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श प्रदान करते हुए आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया। शिविर में रक्तचाप, मधुमेह एवं अन्य सामान्य रोगों की जांच कर मरीजों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया।

मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो० आर० बी० कमल ने वृद्धाश्रम में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के वरिष्ठ नागरिक हमारे अनुभव, संस्कृति एवं मूल्यों के अमूल्य धरोहर हैं। उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। उन्होंने शिविर में सहभागी चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के सेवा कार्य चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की सामाजिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं तथा भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे। 'मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो० ए0 ए0 जाफरी ने वृद्धाश्रम में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे शिविर समाज के वरिष्ठ नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों की नियमित स्वास्थ्य जांच, समय पर उपचार तथा आवश्यक परामर्श से उनके जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य शिविर का आयोजन विभिन्न स्थानों पर समय–समय पर आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ उनके निकट ही उपलब्ध कराया जा सके।

इस अवसर पर चिकित्सक डा0 अमित पटेल, डा0 नितेश कुमार यादव, डा0 निहारिका, डा0 अक्षय सिंह, डा0 संदीप सिंह एवं फार्मासिस्ट व कर्मचारी तथा गिरिजेश राय (संरक्षक), हरिशंकर (प्रधान), रविकुमार (केयर टेकर), महिमा चौबे (केयर टेकर),, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय सदस्य हर्षवर्धन, प्रखर, अक्षत व अर्जुन आदि लोग उपस्थित रहें।

एसबीआई ने अमीनाबाद इंटर कालेज को प्रदान किए 500 स्टील बेंच

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। भारतीय स्ध्टेट बैंक हर भारतीय का बैंक होने का दायित्व निभाते हुए अपने ग्राहकों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के अलावा उन्हें वित्तीय रूप से जागरूक बनाते हुए राष्ट्र निर्माण में एक सहभागी की भघूमिका निभा रहा है। अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत एसबीआई समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर सुधारने और उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता के तहत बैंक से राज्य के कई प्राथमिक विद्यालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों कर वहां अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बैंक ने मंगलवार को नगर निगम, लखनऊ द्वारा संचालित अमीनाबाद इंटर कालेज में अध्ययनरत 2000 छात्रों को बैठने की उत्तम व्यवस्था करते हुए वहां गुणवत्तायुक्त 500 स्टील बेंच प्रदान किए। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्ध्य अतिथि श्रीमती सुषमा खर्कवाल, महापौर, नगर निगम लखनऊ ने कहा कि " बच्चे भविष्य की नींव होते हैं और उनका भविष्य संवारना भगवान के पूजा से बेहतर है। इसलिए हम नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों को बेहतरीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छा स्ध्कूल और मां की परवरिश बच्चों का भविष्य संवारती है।" इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि नगर आयुक्त 'गौरव कुमार ने कहा कि "नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों के सभी कक्षाओं को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।" इस कार्यक्रम में एसबीआई के उप महाप्रबंधक धीरज कुमार ने कहा कि एसबीआई अखिल भारतीय स्ध्तर पर अपने लाभ में से 700 करोड़ से अधिक की राशि समाज के कल्याणकारी कार्यों पर व्यय करती है। बैंक ने प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों के उन्नयन के साथ–साथ सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल के तहत कन्याओं की शिक्षा एवं स्वच्छता की दिशा में अनेकों कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसी क्रम में आज बच्चों की पढ़ाई के लिए 500 स्टील बेंच उपलब्ध कराना हमारे लिए केवल एक औपचारिक दायित्व नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारी संपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। हम आगे में इस दिशा में हर संभव प्रयास करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त श्री अरुण कुमार गुप्ध्ता, उप नगर आयुक्त रश्मि भारती, क्षेत्रीय पार्षद मुकेश सिंह मोंटी एवं सीवीओ महामिलिंद जी के अलावा अमीनाबाद इंटर कालेज के प्राचार्य साहब लाल मिश्र तथा एसबीआई से क्षेत्रीय प्रबंधक अवंतिका सिंह मिश्रा, सरकारी व्यवसाय शाखा की मुख्य प्रबंधक ऋचा द्विवेदी एवं अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

एल.पी.सी., सहारा स्टेटस में ए.एस.आई. एस.सी. कविता लेखन प्रतियोगिता

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। लखनऊ पब्लिक कॉलेज (एलपीसी), सहारा स्टेट्स, जानकीपुरम में प्रतिष्ठित एएसआईएससी नबरून डे मेमोरियल कविता लेखन (जूनियर) प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लखनऊ के 11 प्रमुख विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ डिप्टी डायरेक्टर एवं प्रधानाचार्या मीना टांगरी द्वारा दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। प्रतिभागियों को उम्मीदों की आवाज एवं संगीत की लय विषयों पर कविता लेखन के लिए आमंत्रित किया गया। प्रतियोगिता का मूल्यांकन शिक्षाविद् एवं उद्यमी डॉ. चारू रावत, डॉ. पॉल मैथ्यू तथा प्रीति एम. शाह द्वारा किया गया। परिणामों में माउंट कार्मेल कॉलेज की आरना श्रीवास्तव ने प्रथम स्थान, सेंट एंथनी इंटर कॉलेज के अर्पण द्विवेदी ने प्रथम उपविजेता तथा मॉडर्न एकेडमी की इयासा राय ने द्वितीय उपविजेता का स्थान प्राप्त किया। विजेताओं एवं निर्णायकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन हेडमिस्ट्रेस मनीषा कर्टिस द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

फसाड लाइट से सजेगा घंटाघर चौक और आचार्य नरेंद्रदेव पार्क

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।ऐतिहासिक घंटाघर चौक और सिविल लाइन स्थित स्वतंत्रा स्मारक आचार्य नरेंद्र देव पार्क को अब आर्किटेक्चरल एलईडी फसाड लाइटिंग से सजाया जाएगा। घंटाघर चौक में महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार के साथ समारोहपूर्वक सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ किया। महापौर दोपहर सवा 12 बजे अन्य साथियों के साथ घंटाघर की छत पर पहुंचे और वैदिक रीति–रिवाज से पूजन–अर्चन किया। उन्होंने नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व उप सभापति राजेश गौड़, पार्षद अनिल सिंह, विशाल पाल, धर्मवीर, सोमू यादव, अजय पांडेय, भाजपा नेता आलोक द्विवेदी, संग्राम सिन्हा, नगर निगम के सहायक अभियंता निर्माण राजपति यादव तथा अवर अभियंता प्रकाश जाह्नवी सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडेय ने बताया कि घंटाघर चौक को लाल चौक की तर्ज पर सजाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत घंटाघर पर आर्किटेक्चरल एलईडी फसाड लाइटिंग लगाई जाएगी, जिसे डीएमएक्स कंट्रोल सिस्टम से नियंत्रित किया जाएगा।उन्होंने बताया कि भवन की रूपरेखा को उभारने के लिए एलईडी स्ट्रिप एवं लाइनर लाइटिंग लगाई जाएगी। इसके साथ ही भवन पर नीचे से ऊपर की ओर प्रकाश डालने के लिए अप–लाइटिंग की जाएगी। इससे संध्या और रात्रि के समय घंटाघर चौक का स्वरूप अत्यंत आकर्षक दिखाई देगा। शहरवासी तथा पर्यटक इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि सिविल लाइन स्थित आचार्य नरेंद्र देव पार्क, जहां शहीद स्मारक स्थित है, उसे भी फसाड लाइटिंग से सजाया और संवारा जाएगा।इस मौके पर महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी एवं नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने कृष्णा नगर फेस–2 कॉलोनी का भी निरीक्षण किया।यहां एक गली का स्तर नीचे होने के कारण जलभराव की समस्या बनी रहती थी।स्थानीय अधिवक्ता रामशेखर की शिकायत पर दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद उनकी मांग के अनुरूप गली को ऊंचा करने के लिए निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष सोशल मीडिया पर हो रहे ट्वीट और भ्रामक प्रचार को लेकर कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज करने की दी तहरीर

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।छात्र सभा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवांशु तिवारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर सोशल मीडिया पर हो रहे ट्वीट और भ्रामक प्रचार को लेकर कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी।सपा प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र सभा शिवांशु तिवारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर सोशल मीडिया पर हो रहे ट्वीट को लेकर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को तहरीर देकर यह मांग की सांसद निशिकांत दुबे प्रियंका राय , ग्लोबल भारत टीवी, अखिलेश सिंह अमित भारद्वाज आदि द्वारा अपने एक्स पोस्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर की गई टिप्पणी एवं सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स पर कुछ अज्ञात लोग पूर्व सुनियोजित साजिश के तहत अखिलेश यादव जी के खिलाफ तथ्यहीन अनर्गल एवं मनगढ़ंत वीडियो पोस्ट डाल रहे हैं।प्रवक्ता राकेश यादव के अनुसार जिसमे दावा किया जा रहा है कि राम जन्मभूमि चोरी की मामले में गिरफ्तार टीन्नू यादव से अखिलेश यादव की 980 बार बात हुई है जबकि यह बात पूर्णता तथ्यहीन गलत और मनगढ़ंत है फेसबुक पर पीठाधीश्वर जगतगुरु आचार्य परमहंस तपस्वी छावनी रामघाट अयोध्या द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति वीडियो पर अनर्गल बातें अभद्र शब्दों का प्रयोग कर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जो कि बिल्कुल निराधार एवं मनगढ़ंत है इस वीडियो के माध्यम से कहा गया है कि अखिलेश यादव ईल्म।बताते हैं और टीन्नू यादव माल उड़ाते हैं जो की बहुत ही अशोभनीय है इस मौके पर छात्र सभा उपाध्यक्ष शिवांशु तिवारी ने तहरीर देकर सभी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की है !

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना एवं छात्रों हेतु डीबीटी योजना के साथ ही एसबीआई द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिए जाने का हुआ शुभारंभ

अयोध्या।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्रदान करने व अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत नियमित, मानदेय, स्व वित्त पोषित, अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक,

शिक्षा मित्र, अनुदेशकों एवं विद्यालय में कार्यरत रसोइयों, अन्य शिक्षक, शिक्षिकाओं को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ तथा एसबीआई के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी सभी बच्चों के लिए डीबीटी योजना का शुभारंभ किया।इसी कड़ी में जनपद अयोध्या के सर्किट हाउस में मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, विशिष्ट अतिथि महापौर नगर निगम महंत गिरीश पति त्रिपाठी जी, भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी,विधायक रुदौली रामचंद्र यादव, जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक पवन कुमार तिवारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लाल चन्द्र की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप शाही द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ।इस मौके पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी द्वारा मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप शाही को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया गया। मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह द्वारा महापौर गिरीश पति त्रिपाठी को बुके भेंट कर उनका स्वागत किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह को बुके भेंट कर उनका स्वागत जिला विद्यालय निरीक्षक पवन कुमार तिवारी जी द्वारा किया गया।भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी जी का स्वागत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बुके भेंट इसके किया गया।इसके पश्चात सभी विशिष्ट अतिथियों द्वारा आज के मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना और डीबीटी योजना के बारे में किए जा रहे शुभारंभ के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप शाही ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वह सीएम योगी आदित्यनाथ से समय के अनुशासन को अवश्य सीखें जिस प्रकार आज का कार्यक्रम समयबद्ध ढंग से पूरा हो रहा है, इसी तरह प्रतिदिन स्वयं समय से विद्यालय पहुंचकर एवं बच्चों को समय से बुलाकर विद्यालय गतिविधियों को संपन्न कराएं।बच्चों का मन घर से ज्यादा विद्यालय में लगे ऐसा स्वच्छ परिवेश विद्यालय का होना चाहिए।कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ के अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों 10 शिक्षकों को मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का कार्ड वितरित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया।इसी के साथ ही मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप शाही ने माध्यमिक विद्यालयों के भी 10 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना का कार्ड वितरित किया।बेसिक शिक्षा विभाग से धीरज शुक्ला, क्षमा जायसवाल राकेश कुमार जायसवाल, बृजेश कुमार, कृष्ण कुमार पांडे, विनय कुमार गुप्ता, शिवम सिंह, अनूप दुबे और सविता शुक्ला को मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप शाही के हाथों मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का कार्ड प्रदान किया गया।

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिस कर्मियों ने महिलाओ को किया जागरूक

अयोध्या।बुधवार को मिशन शक्ति अभियान फेज–5 के तहत महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला के नेतृत्व मे महिला उप निरीक्षक सोनी व अन्य पुलिस कर्मियों ने जिला महिला चिकित्सालय,जिला पुरुष चिकित्सालय, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन सहित अन्य प्रमुख चौराहों तथा मार्गों पर मिशन शक्ति अभियान फेज – 5 के तहत महिलाओ व अन्य लोगो को जागरुक किया है।इस मौके पर उन्होंने महिलाओ व बेटियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओ के प्रति जागरूक व सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी दिया।उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन

नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।इस मौके पर सायरा बानो, रोशनी सहित अन्य महिला पुलिस कर्मी मौजूद रही।

'वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा की, रेस्टोरेशन में लापरवाही पर जताई नाराजगी'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंगलवार को विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने जल निगम ग्रामीण एवं शहरी द्वारा कराए जा रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और पेयजल पाइपलाइन बिछाने के बाद रेस्टोरेशन कार्य में लापरवाही तथा सभी घरों तक जलापूर्ति सुनिश्चित न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। मा० मंत्री ने जल निगम ग्रामीण और संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि रेस्टोरेशन कार्य और हर घर तक पेयजल पहुंचाने का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। नगर क्षेत्र में पाइपलाइन डालने के बाद रेस्टोरेशन कार्य में हो रही देरी पर भी मा० मंत्री ने असंतोष जताते हुए कार्यदायी संस्था को 20 जुलाई तक

सभी लंबित रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में पार्षदों ने अपने–अपने वार्डों में पाइपलाइन बिछाने के बाद खराब सड़कों और अधूरे रेस्टोरेशन का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री ने संबंधित संस्था को एक सप्ताह के भीतर सभी शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भविष्य में जहां भी नई पेयजल पाइपलाइन डाली जाए, वहां उसी के साथ तत्काल रेस्टोरेशन कार्य भी कराया जाए, ताकि सड़कें पहले जैसी स्थिति में दिखाई दें और नागरिकों को परेशानी न हो। बैठक में जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने जल निगम शहरी एवं ग्रामीण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी, मुख्य विकास अधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी, डीएफओ सचिन कुमार, संबंधित विभागों के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि एवं पार्षद उपस्थित

ट्रेन पर पत्थर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार

अयोध्या।मंगलवार की रात गाड़ी संख्या 12225 कैफियत ट्रेन पर पत्थर बाजी करने वाले एक आरोपी को आरपीएफ व जीआरपी पुलिस कर्मियों ने गिरफ्तार किया।इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक आफ हरीश कुमार शाही ने बताया कि मंगलवार को देर रात्रि में समय लगभग 20ः45 बजे गाड़ी संख्या 12225 कैफियत एक्सप्रेस पर रेलवे स्टेशन सोहावल के पास एक व्यक्ति द्वारा पत्थर मारे जाने की सूचना मिली।इसकी सूचना मिलते ही पर आरपीएफ एएसआई पंकज सिंह व एएसआई रमेश कुमार यादव,उप निरीक्षक जीआरपी संजय अग्निहोत्री ने त्वरित करते हुए घटनास्थल

सोहावल रेलवे स्टेशन के आस पास के एरिया में ट्रैक के किनारे अथक खोजबीन किया।बताया कि घटना करने वाले आरोपी पिंटू पुत्र स्व राम शरण निवासी ग्राम कतरौली थाना रौनाही जिला अयोध्या को गिरफ्तार किया।

आरपीएफ कर्मियों द्वारा कैंट रेलवे स्टेशन पर जागरुता अभियान चलाकर रेल यात्रियों को किया जागरूक

अयोध्या।प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ कैंट रेलवे स्टेशन हरीश कुमार शाही के नेतृत्व में तथा उप निरीक्षक रचना यादव की सक्रिय निगरानी में पिछले दिनों से कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।इस मौके आरपीएफ उप निरीक्षक रचना यादव अपनी टीम के साथ स्टेशन परिसर,सभी प्लेटफार्मों एवं ट्रेनों में यात्रियों को अनावश्यक चेन पुलिंग से होने वाले नुकसान,सामान चोरी से बचाव,जहरखुरानी गिरोहों की गतिविधियों तथा ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने के खतरों के प्रति जागरूक करते हुए दिखाई दी।बताते चले कि आगामी श्रावण मास और रामनगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ को देखते हुये यह अभियान सुरक्षा की दृष्टि से चलाया जा रहा है।इस मौके पर सुरक्षा कर्मी यात्रियों को यह भी समझा रहे है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, लावारिस वस्तु अथवा आपात स्थिति की सूचना तत्काल रेलवे हेल्पलाइन एवं आरपीएफ को दें। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक कैंट रेलवे स्टेशन हरीश कुमार शाही तथा उप निरीक्षक रचना यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि रेल यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि से जागरूक किया जा रहा है,वही स्टेशन परिसर के सभी प्लेटफॉर्मों,प्रतीक्षालय, रेलवे सर्कुलेटिंग एरिया,आरक्षण केंद्रों तथा ट्रेनों में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए भी यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार चलेगा।

निषादराज बोट सब्सिडी योजना का पोर्टल पर आनलाइन आवेदन 09 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण अयोध्या सुषमा निषाद ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में मत्स्य विभाग द्वारा संचालित राज्य सेक्टर की विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना,निषादराज बोट सब्सिडी योजना एवं सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना योजना के अन्तर्गत जनसामान्य को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विभागीय पोर्टल 'जिजचरूध्धपीमतपमे.नच.हवअ.पद दिनॉक 08.06.2026 से दिनॉक 28.06.2026 तक खोला गया था।निषाद राज बोट सब्सिडी योजना में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु 'पोर्टल दिनॉक 09.07.2026 से दिनॉक 24.07.2026 तक पुन खोला जा रहा है। योजनान्तर्गत परियोजना का विवरण इकाई लागत, आवेदन करने की प्रक्रिया,आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख व विस्तृत विवरण को विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उक्त योजनाओं में यदि भविष्य में कोई संशोधन होता है तो संशोधित प्राविधान लागू होंगे।योजना में पूर्व के वर्षों में निरस्त/प्रतीक्षारत आवेदन वाले आवेदक पुनः आवेदन कर सकते है। उक्त से सम्बन्धित समस्त जानकारी जनपदीय कार्यालय मत्स्य विभाग, अयोध्या से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

डीएम ने पर्यटन विभाग के संचालित निर्माण कार्यों के तहत चौक स्थित एतिहासिक द्वार व साकेत सदन का किया निरीक्षण

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने पर्यटन विभाग के अन्तर्गत संचालित निर्माण कार्यो के तहत अयोध्या शहर के चौक स्थित एतिहासिक द्वार के सौंदर्यीकरण के कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया।उन्होंने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि सौंदर्यीकरण के दौरान इसको पूर्व की भांति संरक्षित किया जाएं और कार्य में तेजी लाते हुये शीघ्र पूर्ण किया जाएं।इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोतवाली के पास स्थित गेट नं0 –4 में आवागमन हेतु 02 मार्गों में से एक–एक मार्ग को बन्द कर अवशेष कार्य को शीघ्र –अतिशीघ्र गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिये गये साथ ही निरीक्षण के समय नगर कोतवाली के प्रभारी को भी कार्य में सहयोग हेतु रास्ते के नियमानुसार डायवर्जन के लिए निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी ने द्वारा रोड स्थित साकेत सदन के मुख्य भवन (बी–1), इन्ट्रेस प्लाजा, सोविनियर शाप (बी–2) इत्यादि निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण करते हुये लम्बित कार्यों को समय पर पूर्ण करने तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने उप निदेशक पर्यटन को हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रक्रिया में लाने के निर्देश दिये।इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह, उप निदेशक पर्यटन बी पी सिंह सहित यू0पी0प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई–11, अयोध्या के सहायक परियोजना प्रबन्धक व अवर अभियन्ता एवं सम्बन्धित फर्म के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

बीकापुर तहसील में 15 दिन से नकल खतौनी ना मिलने से आमजन परेशान

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। बीकापुर तहसील में खतौनी की नकल समय पर जारी न होने से किसानों,अधिवक्ताओं और अन्य आवेदकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।स्थानीय लोगों ने तहसील कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए व्यवस्था में सुधार और शीघ्र समाधान की मांग की है। जबकि इस समय किसान फार्मर रजिस्ट्री सहकारी समितियों में खाद के लिए तथा गन्ना समितियां में सदस्य बनने के लिए भी खतौनी की किसानों को जरूरत पड़ रही है लेकिन इस समय तहसील के अधिकारी मौन है और शासन की मानसा पर पानी फेर रहे है उत्तर प्रदेश में खतौनी की नकल की सुविधा राजस्व विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

ओमैक्स लिमिटेड 5 राज्यों मे प्रस्तावित 19 होटलों मे से उत्तर प्रदेश मे अयोध्या सहित 12 प्रमुख महानगरों,तीर्थ स्थलों पर खोलेगी एक दर्जन होटल

OMAXE
Turning dreams into reality

ब्यूरो चीफ राजेश कुमार श्रीवास्तव

अयोध्या।देश की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी ओमैक्स लिमिटेड ने हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में प्रवेश की घोषणा की है।कंपनी अगले 4–5 वर्षों में लगभग 6,200 करोड़ रुपये के निवेश से पांच राज्यों में 19 होटल विकसित करेगी।इन परियोजनाओं का कुल क्षेत्रफल करीब 50 लाख वर्ग फुट होगा।कंपनी के अनुसार,इस निवेश का उपयोग तेजी से विकसित हो रहे शहरों, प्रमुख तीर्थस्थलों और महत्वपूर्ण यात्रा मार्गों पर हॉस्पिटैलिटी परियोजनाएं विकसित करने के लिए किया जाएगा।कंपनी इन हॉस्पिटैलिटी परियोजनाओं को अपनी मौजूदा टाउनशिप, मिश्रित उपयोग (मिक्स्ड–यूज) परियोजनाओं, व्यावसायिक परिसरों और शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के साथ जोड़ेगी।आने वाले समय मे प्रस्तावित 19 होटलों में से 12 होटल उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। इनमें अयोध्या में दो, लखनऊ में तीन, प्रयागराज, गाजियाबाद और गोरखपुर में एक–एक, कौशांबी में दो तथा वृंदावन में दो होटल शामिल हैं।इसके अलावा नई दिल्ली, फरीदाबाद और उज्जैन में एक–एक होटल विकसित किया जाएगा। वहीं चंडीगढ़, अमृतसर और लुधियाना में कुल चार होटल बनाए जाएंगे।जिनमें चंडीगढ़ में दो होटल शामिल होंगे।इस तरह अगले 4–5 वर्षों में ओमैक्स की मौजूदगी पांच राज्यों के 13 शहरों तक पहुंच जाएगी।कंपनी की प्रमुख परियोजनाओं में नई दिल्ली के द्वारका स्थित श्द ओमैक्स स्टेट्स में आईएचसीएल (आईएचसीएल) के श्गेटवेश ब्रांड का 158 कमरों वाला होटल भी शामिल है।50.4 एकड़ में फैली यह एकीकृत परियोजना दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित की जा रही है।इसके अलावा, ओमैक्स उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के साथ अपनी पीपीपी परियोजनाओं के तहत यात्रा मार्गों (ट्रांजिट) पर आधारित हॉस्पिटैलिटी अवसंरचना भी विकसित करेगा।कंपनी का कहना है कि इस विस्तार से उसकी मौजूदा परियोजनाओं को बेहतर सहयोग मिलेगा और नियमित आय (रिकरिंग रेवेन्यू) के स्रोत भी और मजबूत होंगे।ओमैक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मोहित गोयल ने बताया कि,श्हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में विस्तार हमारी एकीकृत विकास रणनीति का स्वाभाविक हिस्सा है।बेहतर होती कनेक्टिविटी, धार्मिक पर्यटन में बढ़ोतरी और उभरते शहरों में यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए इन स्थानों पर गुणवत्तापूर्ण हॉस्पिटैलिटी सुविधाओं की आवश्यकता है।इस विस्तार के जरिए हमारा लक्ष्य ऐसे अच्छी जगहों पर स्थित होटल और हॉस्पिटैलिटी केंद्र विकसित करना है, जो हमारी मौजूदा परियोजनाओं के पूरक बनें,नियमित आय को मजबूत करें और जिन शहरों में हम काम कर रहे हैं वहां आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दें।श्कंपनी का यह हॉस्पिटैलिटी पोर्टफोलियो व्यावसायिक यात्राओं, अवकाश पर्यटन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन यात्राएं, सम्मेलन और प्रदर्शनियां) तथा धार्मिक पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगा।इसके तहत मिड–स्केल और अपस्केल ब्रांडेड होटल, लग्जरी और प्रीमियम होटल, अधिक क्षमता वाले तीर्थस्थल होटल, ब्रांडेड सर्विस्ड अपार्टमेंट और लंबे समय तक ठहरने के लिए स्टूडियो आवास (एक्सटेंडेड–स्टे स्टूडियो) विकसित किए जाएंगे।प्रत्येक परियोजना को संबंधित शहर की पर्यटन क्षमता और स्थानीय मांग के अनुसार तैयार किया जाएगा।कंपनी अगले 4–5 वर्षों में इस निवेश को चरणबद्ध तरीके से करेगी। सभी परियोजनाएं पूरी तरह संचालित होने के बाद हॉस्पिटैलिटी कारोबार से करीब 1,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व मिलने की उम्मीद है।यह अनुमान परिचालन के शुरुआती पांच वर्षों के औसत प्रदर्शन के आधार पर लगाया गया है।ओमैक्स ने बताया कि फिलहाल वह देश और विदेश की प्रमुख हॉस्पिटैलिटी कंपनियों के साथ ब्रांडिंग और होटल प्रबंधन को लेकर उन्नत स्तर की बातचीत कर रही है।अंतिम समझौते होने के बाद इन साझेदारियों की औपचारिक

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार-पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।